of medicines are unavoidable if their availability is to be ensured. However, the increae is not to the extent indicated in the question.

(b) The Drugs Policy, including DPCO, 1987, is under active review of the Government.

(c) to (e) There are no reports regarding the wide-spread shortage of any life saving essential drug. In so far as pricing of medicines are concerned, price revisions of price controlled drugs/formulations are approved on the basis of recommendations of BICP as per the provisions of DPCO, 1987, and after careful scrutiny in the Department. In the case of formulations outside price control as and when any unreasonable price increase is noticed, Government intervenes to bring it to a reasonable level. With this approach, overall availability of drugs at reasonable prices has been ensured.

Setting up of an Atomic power station in Kerala

1145. SHRI M.A. BABY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an atomic power station in Kerala;

(b) if so, the details thereof and the decision regarding the site of the project;

(c) whether Government of Kerala have submitted any proposal in this regard;

(d) whether Government are aware of certain objections raised by the various organisations of the State; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) No, Sir. There is no proposal in the eighth five year plan.

(b) Does not arise.

(c) Kerala State Authorities proposed a number of sites for setting up of an atomic power station. Preliminary investigations on these sites were carried out by a Technical Committee constituted by the Department of Atomic Energy (DAE). Presently, a Site Selection Committee constituted by the DAE is reviewing the work done by the Technical Committee. This is part of the ongoing site investigations to meet the future needs of the nuclear power programme.

(d) Yes, Sir.

(e) Selection of sites for nuclear power plants is made only after a detailed review of site characteristics by Atomic Energy Regulatory Board on safety aspects, Union Ministry of Environment and Forests on environmental angle and the approval by the Government. All safety and environmental aspects are given due consideration before selecting any site in the country.

विकासात्मक कार्यों में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना

1146. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पैदा की जा रही परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः परमाणु विद्युत रिएक्टरों से बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थापित अनुसंधान रिएक्टरों का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा से कई नए उत्पाद/प्रक्रियाएं विकसित किए जाते हैं जिनका उपयोग नाना प्रकार के विकास संबंधी कार्यकलापों में किया जा रहा है, जैसे कि चिकित्सा, कृषि तथा उद्योग में रेडियो आइसोटोपों का अनुप्रयोग खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग औषध तथा अन्य चिकित्सा उत्पादों का विकिरण से निर्जर्मीकरण, विभिन्न रोगों का निदान करने के लिए काम में लाई जाने वाली रेडियो इम्यनो विश्लेषण तकनीकों का विकास, भूजल का शोधन करने के लिए विकिरण सुविधा, उद्योग, आदि में गामा रेडियोग्राफी का उपयोग तथा न्यूट्रॉन उत्प्रेरण विश्लेषण जैसी कई परिष्कृत तकनीकों जिनके विविध अनुप्रयोग हैं का विकास भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में किया गया है । इनके अलावा, कई महत्वपूर्ण किस्म की आधुनिकतम प्रौद्योगिकियां जिनके व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, भी विकसित की गई हैं और उन्हें गैर-सरकारी तथा सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों को अंतरित किया गया है । इन सभी प्रौद्योगिकियों के विकास ने पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत करने में, देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में, और सामान्य रूप से लोगों के कल्याण में योगदान दिया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

1147. **मौलाना अबेदुल्ला खान आज़मी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यकलापों का निजीकरण किए जाने की कोई योजना नहीं है । तथापि, विभाग के अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों में से प्रौद्योगिकी का अंतरण बिना एकाधिकार आधार पर निजी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दोनों को करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है । ये कार्य असंवेदनशील क्षेत्रों से संबद्ध हैं।

Priority areas of atomic energy in the eighth five year plan period

1148. **SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what would be the major thrust areas of the Atomic energy development programme in the Eighth Five Year Plan period; and

(b) what would be the fuel requirements and how Government propose to meet them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) A major thrust area of the Atomic Energy development programme in the eighth five year plan is generation of electricity through nuclear power. As per the proposal of the Department of Atomic Energy a total capacity of 7700 MWe is envisaged to be set up by the year 2002 AD including 2000 MWe installed capacity as par the Inter-Governmental Agreement signed between erstwhile USSR and India in November, 1988. In addition to concerted efforts towards augmentation of nuclear power, other thrust areas would be research in lasers, accelerators, cyclotron, super conductors, remote handling/robotics, advanced